भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1759
04 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

सैन्य निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता के संपूर्ण मूल्यांकन के लिए व्यापक प्रणाली

1759. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सैन्य निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता के समग्र मूल्यांकन हेतु कोई प्रणाली स्थापित करने का विचार रखती है, जिसमें सभी सैन्य निर्माण परियोजनाओं के मूल्यांकन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक केंद्रीकृत एजेंसी की स्थापना भी सम्मिलित है;

(ख) क्या इस संबंध में मंत्रालय ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सैन्य निर्माण नीतियों एवं विनियमों का अध्ययन कर उनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की हैं;

(ग) क्या सरकार सैन्य निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष विधेयक लाने का विचार रखती है; और

(घ) क्या मंत्रालय सैन्य निर्माण परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु अधिक ठेकेदारों को आकर्षित करने की योजना बना रहा है, ताकि कार्टेल से बचा जा सके और सरकार की सौदेबाजी की शक्ति में इज़ाफा हो सके?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): जी, नहीं। रक्षा निर्माण के सभी कार्य मुख्यत: सैन्य अभियान्त्रिकी सेवा (एमईएस) द्वारा केंद्रीकृत एजेंसी के तौर पर निष्पादित किए जाते हैं एवं यह व्यवस्था अन्य विकसित देशों के समान है। रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति, नियमों एवं विनियमों का पालन एमईएस पहले से ही इस उद्देश्य से करता है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता बनी रहे।

(ग): जी, नहीं।

(घ): एमईएस के पास पहले से ही अधिक ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने की और खुली निविदा की प्रणाली मौजूद है।

*****